वी. मेकला

बनाम

एम. मैलाथी और ए.एन.आर.

(सिविल अपील संख्या 4880/2014)

25 अप्रैल, 2014

[ज्ञान सुधा मिश्रा और वी. गोपाल गौड़ा, जे.जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:

धारा 166-मोटर दुर्घटना-न्यायसंगत एवं उचित मुआवजा-16 वर्षीय मेधावी छात्र स्थायी रूप से विकलांग हो गया-'आय की हानि', 'दर्द और पीड़ा', 'सुविधाओं की हानि', 'विवाह के आनंद की हानि' आदि मद के तहत मुआवजा।-माना गया: चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर उच्च न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलकर्ता को 70% स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा है-हालाँकि, 6,000/- की मासिक अनुमानित आय के संबंध में नीचे की अदालतों की धारणा निचले स्तर पर है-अपीलकर्ता एक मेधावी छात्रा है क्योंकि उसने 10वीं कक्षा में प्रथम रैंक हासिल की है, शैक्षिक करियर और रोजगार की संभावनाओं के मामले में उसका भविष्य बेहतर होता, जो उसके स्थायी रूप से विकलांग होने के परिणामस्वरूप खो गया है-इसलिए, उचित और उचित गणना के लिए मुआवज़ा, 'आय की

हानि' मद के तहत, उसकी मासिक आय रुपये 10,000/- के रूप में ली जाएगी। और इसका 50% आय की भविष्य की संभावनाओं के लिए जोड़ा जाएगा-दर्द और पीड़ा के लिए मुआवजा बढ़ाकर 2,00,000/- किया जाएगा-सुविधा और परिचारक शुल्क के नुकसान के तहत मुआवजा बढ़ाकर रु. 2,00,000/- रुपये कर दिया गया है। जीवन के आनंद के नुकसान और विवाह की संभावनाओं के मद में मुआवजा बढ़ाकर 3,00,000/- रुपये कर दिया गया है। बैसाखी खरीदने के लिए 50,000/- रुपये और मुकदमे की लागत के लिए 25,000/- रुपये भी दिए गए हैं-इस प्रकार, अपीलकर्ता आवेदन की तारीख से भुगतान तक 9% ब्याज के साथ 30,93,000/- रुपये के कुल मुआवजे का हकदार है।

धारा 166-मोटर दुर्घटना दावा-निपटान में ली गई अवधि-मुद्रास्फीति का प्रभाव-निर्विवाद तथ्य को ध्यान में रखते हुए तथ्य यह है कि दुर्घटना के बाद से धन की मुद्रास्फीति हुई है इसे ट्रिब्यूनल और अपीलीय अदालत द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुसार दावेदार अपीलकर्ता को मुआवजा देते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अपीलकर्ता, अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 11 वीं कक्षा की 16 वर्षीय छात्रा, एक दुर्घटना का शिकार हो गई और गंभीर चोटों के कारण वह स्थायी रूप से विकलांग हो गई। ट्रिब्यूनल ने उसे 6,46,000 रुपये का मुआवजा दिया और उच्च न्यायालय ने इसे बढ़ाकर रु.

18,22,000/- कर दिया । दावेदार ने यह कहते हुए तत्काल अपील दायर की कि उच्च न्यायालय ने उसकी अनुमानित आय 6,000 रुपये प्रति माह के रूप में लेने में गलती की। यह उसका मामला था कि वह एक प्रतिभाशाली छात्रा थी और पेशेवर डिग्री प्राप्त कर सकती थी और कम से कम 18,000/- रुपये प्रति माह कमा सकती थी।

अदालत के समक्ष विचार के लिए प्रश्न यह था: क्या दावेदार-अपीलकर्ता इन मदों अर्थात् आय की हानि, दर्द और पीड़ा, सुविधाओं की हानि, विवाह की संभावनाओं का आनंद की हानि और बैसाखी की लागत के तहत मुआवजे में वृद्धि का हकदार था?

अदालत ने अपील की अनुमति दी

अभिनिर्धारित किया:

1.1. दावेदार-अपीलकर्ता की जांच करने पर, डॉक्टर-पीडब्लू2 ने राय दी कि वह बैठने में सक्षम नहीं है, उसकी विकलांगता 70% है। पीडब्लू 2 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि अपीलकर्ता के दोनों पैरों की हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया है, घुटने को मोड़ने में असमर्थ है, और पैरों को पूरी तरह से नहीं खींचा जा सकता है और घुटने की हड्डियां ठीक से जुड़ी नहीं हैं और अपीलकर्ता बिना बैसाखी के चल नहीं सकता है। डॉक्टर ने यह भी कहा है कि अपीलकर्ता को चलते समय गंभीर दर्द हो रहा है और इसके अलावा अपीलकर्ता के दोनों पैरों की मोटाई भी कम हो गई है। PW2 के

साक्ष्य को ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। रिकॉर्ड पर मौजूद चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर उच्च न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलकर्ता 70% स्थायी विकलांगता से पीड़ित है। [पैरा 5,12 बी और 14] [781-ई; 785-जी-एच; 786-ए-बी; 787-ए-बी]

राज कुमार बनाम अजय कुमार और अन्य। 2010 (13) एससीआर 179 = (2011) 1 एससीसी 343-पर निर्भर।

1.2. हालाँकि, 6,000/- की मासिक अनुमानित आय के संबंध में नीचे दी गई अदालतों की धारणा निचले स्तर पर है। अपीलकर्ता एक मेधावी छात्रा है क्योंकि उसने 10वीं कक्षा में प्रथम रैंक हासिल की है, उसके पास व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में बुनियादी या मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए शैक्षिक करियर के मामले में बेहतर भविष्य होता और उसे एक उपयुक्त सार्वजनिक या निजी रोजगार मिल सकता था। लेकिन दुर्घटना में लगी चोटों के कारण वह स्थायी विकलांगता के कारण वह अवसर खो गई है और इसलिए, वह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार मुआवजे की हकदार है। [पैरा 14-15] [787-बी-सी, 788-ए-सी]

आर.डी. हट्टंगडी बनाम पेस्ट कंट्रोल (इंडिया) प्रा. लिमिटेड एवं अन्य। 1995 (1) एससीआर 75 = (1995) 1 एससीसी 551; गोविंद यादव बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2011) 10 एससीसी 683; और

राज कुमार बनाम अजय कुमार और अन्य। 2010 (13) एससीआर 179 = (2011) 1 एससीसी 343-पर निर्भर।

1.3. इसके अलावा, इस निर्विवाद तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दुर्घटना की घटना के बाद से धन की मुद्रास्फीति/मंहगाई हुई है, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुसार दावेदार-अपीलकर्ता को मुआवजा देते समय ट्रिब्यूनल और अपीलीय अदालत द्वारा इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। [पैरा 16] [788-सी-डी]

गोविंद यादव बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2011) 10 एससीसी 683; और रेशमा कुमारी बनाम मदन मोहन 2009 (11) एससीआर 305 = (2009) 13 एससीसी 422-पर निर्भर।

1.4. जहां तक प्रतिवादी नंबर 2 की दलील का संबंध है कि अपीलकर्ता अभी भी अपनी शिक्षा पूरी कर सकती है और रोजगार पा सकती है और इसलिए, 'आय की हानि' और 'भविष्य की संभावनाओं' के मद में मुआवजे की राशि बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह ध्यान रखना उचित है कि दावेदार/अपीलकर्ता को दुर्घटना के कारण काफी दर्द और पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है, जिससे उसके दोनों पैर बेकार हो गए हैं। इससे उसकी शादी सहित भविष्य की संभावनाओं की गुंजाइश काफी कम हो गई है। इसके अलावा, एक अपकृत्यकर्ता दावेदार-अपीलकर्ता के कैरियर की शर्तों को निर्धारित करने का हकदार नहीं है। [पैरा 17] [789-बी-डी]

के. नरसिम्हा मूर्ति बनाम प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य। आईएलआर 2004 कर्नाटक 2471-पर निर्भर।

1.5. रेशमा कुमारी के मामले में निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में, इस न्यायालय के लिए अपीलकर्ता के पिछले परिणामों को ध्यान में रखते हुए, आय की हानि की मद में उचित और उचित आय की गणना के लिए उसकी मासिक अनुमानित आय के रूप में 10,000/- लेना उचित और उचित होगा। इसके अलावा, उच्च न्यायालय इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर आय की भविष्य की संभावनाओं पर विचार करने में विफल रहा है। इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा इस शीर्ष के तहत भी पुनः वृद्धि की मांग करना उचित है और इस न्यायालय का मानना है कि दावेदार-अपीलकर्ता, संतोष देवी के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुसार इस शीर्ष के तहत 50% वृद्धि का हकदार है। इसलिए, दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, इस मद के तहत मुआवजे की कुल राशि 22,68,000/- रुपये आंकी गई है। [पैरा 19] [791-सी-ई; 792-जी]

संतोष देवी बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य। 2012 (3) एससीआर 1178 (2012) 6 एससीसी 421-पर निर्भर।

1.6. ट्रिब्यूनल द्वारा पारित पंचाट के साथ समवर्ती निष्कर्ष दर्ज करने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा पीड़ा और मानसिक पीड़ा का फैसला सुनाया गया। हालाँकि, नीचे दी गई अदालतों ने इस मद के तहत 1,00,000/- का

पंचाट देते समय अपीलकर्ता को हुई स्थायी विकलांगता की प्रकृति को दर्ज नहीं किया है, जो बहुत कम राशि है और इस अदालत के निर्णयों के विपरीत है। इसलिए, इस मद के तहत दी जाने वाली राशि को 2,00,000/- तक बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर-पीडब्ल्यू 2 ने राय दी है कि बैसाखी के सहारे चलने के समय, दावेदार-अपीलकर्ता को स्थायी रूप से दर्द होगा। [पैरा 20] [792-जी-एच; 793-ए,एफ]

1.7. सुविधा और परिचर की हानि, नीचे की अदालतों द्वारा 1,00,000/- का जुर्माना भी बहुत कम राशि है क्योंकि अपीलकर्ता ने अपने दोनों पैरों की सुविधा स्थायी रूप से खो दी है। जीवन भर चलने, बैठने, दौड़ने और पढ़ाई के लिए और विशेष रूप से बढ़ती उम्र में उसे एक सहायक की आवश्यकता होगी। इसलिए, गोविंद यादव मामले में इस अदालत द्वारा निर्धारित सिद्धांत के आधार पर इस मद के तहत मुआवजे को 1,00,000/- से बढ़ाकर 2,00,000/- करने की आवश्यकता है। [पैरा 21] [793- जी-एच; 794-ए-बी]

1.8. 'जीवन के आनंद की हानि और विवाह की संभावनाओं' के मद में दी गई 2,00,000/- की मुआवजे की राशि पूरी तरह से अपर्याप्त है क्योंकि अपीलकर्ता की शादी की संभावना काफी हद तक कम हो गई है और स्थायी विकलांगता के कारण वह जीवन के आनंद से वंचित हो जाएगी। अतः मुआवज़ा 2,00,000/- से बढ़ाकर 3,00,000/- करना उचित

एवं उचित होगा। जहां तक समय-समय पर बैसाखी खरीदने की बात है तो 50,000/- की राशि का पंचाट देना न्यायोचित और उचित होगा। [पैरा 22] [794-डी-एफ]

1.9. इसके अलावा, दुर्घटना 11.4.2005 को हुई थी और दावेदार-अपीलकर्ता तब से न्याय के लिए लड़ रहा है। इसलिए, वह 'मुकदमेबाजी की लागत' की सही हकदार है, जिसका मूल्यांकन 25000/- है। [पैरा 23] [794-एफ-एच]

बलराम प्रसाद बनाम कुणाल साहा एवं अन्य। (2014) 1 एससीसी 384-पर निर्भर।

1.10. इस प्रकार, दावेदार-अपीलकर्ता आवेदन दाखिल करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक प्रति वर्ष 9% ब्याज के साथ मुआवजे के रूप में 30,93,000/- की कुल राशि का हकदार है। बीमा कंपनी निर्देशानुसार राशि जमा करेगी। [पैरा 24 और 25] [795-ए-सी]

दिल्ली नगर निगम, दिल्ली बनाम उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन और अन्य। 2011 (16) एससीआर 1 = (2011) 14 एससीसी 481-पर निर्भर।

केस कानून संदर्भ:

2012 (3) एससीआर 1178 पर निर्भर	पैरा 3
1995 (1) एससीआर 75 पर निर्भर	पैरा 5

(2011) 10 एससीसी 683 पर निर्भर पैरा 6

2010 (13) एससीआर 179 पर निर्भर पैरा 13

2009 (11) एससीआर 305 पर निर्भर पैरा 16

आईएलआर 2004 कर्नाटक 2471 पर निर्भर पैरा 17

(2014) 1 एससीसी 384 पर निर्भर पैरा 23

2011 (16) एससीआर 1 पर निर्भर पैरा 24

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4880/2014

सीएमए संख्या 2131/2008 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 31.08.2012 से।

अपीलकर्ता की ओर से टी. हरीश कुमार।

प्रतिवादी की ओर से मंजीत चावला।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

वी. गोपाल गौड़ा, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील घायल-दावेदार द्वारा प्रस्तुत की गई है क्योंकि वह सी.एम.ए. 2008 की संख्या 2131 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और पंचाट दिनांक 31.8.2012 से व्यथित थी। अपने दावे के औचित्य में विभिन्न तथ्यों और आधारों का आग्रह करते हुए विभिन्न

शीर्षकों के तहत भले ही मुआवजे को 6,46,000/- रुपये से 18,22,000/- रु. दावा याचिका दायर करने की तारीख से 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ बढ़ा दिया है

3. दावेदार-अपीलार्थी उच्च न्यायालय द्वारा 18,000/- रु. प्रति माह की जगह मात्र 6,000/- रु. प्रति माह की राशि लेकर मृतक की मासिक काल्पनिक आय का निर्धारण करने से व्यथित है। क्योंकि वह 11 वीं कक्षा में पढ़ रही छात्रा है और अपने स्कूल में प्रथम स्थान पर है। उसके सामने एक उत्कृष्ट करियर था लेकिन उस दुर्घटना के कारण उसे गंभीर चोटें आईं और वह स्थायी रूप से विकलांग हो गई। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पूनमल्ली (संक्षेप में "न्यायाधिकरण") और साथ ही मद्रास उच्च न्यायालय दोनों ही मामले के सभी प्रासंगिक कानूनी पहलुओं पर विचार करने में विफल रहे, अर्थात्, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दुर्घटना में लगी चोटों के कारण दावेदार-अपीलकर्ता को स्थायी पूर्ण विकलांगता का सामना करना पड़ा, उसकी भविष्य की आय की हानि का आकलन इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए था कि दुर्घटना के समय उसकी उम्र 16 वर्ष थी और वह एक मेधावी छात्रा थी और हो सकती थी। पेशेवर डिग्री हासिल की और सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी हासिल की, जिससे कम से कम उसने 18,000/- रुपये प्रति माह की कमाई की होगी। साथ ही, वेतन, महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि और पदोन्नति लाभों में संशोधन की भविष्य की संभावनाएं भी उसके द्वारा

अर्जित की जा सकती थीं। हालाँकि, मालिक-प्रतिवादी के वाहन के चालक की जल्दबाजी और लापरवाही के कारण हुई दुर्घटना के कारण वह आरामदायक आजीविका चलाने के लिए अपनी संभावित आय से वंचित हो गई है क्योंकि वह स्थायी रूप से अक्षम हो गई है, यह कानूनी और तथ्यात्मक पहलू है ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया है। इसलिए, उन्होंने संतोष देवी बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य, के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर भरोसा किया। उसकी उम्र को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की संभावनाओं का 50% ट्रिब्यूनल और अपीलीय न्यायालय दोनों द्वारा अनुमानित मासिक आय में जोड़ा जाना चाहिए था जिसे कमाई के नुकसान के निर्धारण के लिए तय किया जा सकता था जैसा कि उसके पास था उसने अपनी कमाई की क्षमता खो दी क्योंकि वह स्थायी रूप से विकलांग हो गई है। इसलिए, कमाई के नुकसान की इस मद के तहत मुआवजे को काफी बढ़ाया जाना आवश्यक है।

4. दावेदार-अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वकील द्वारा लागू किया जाने वाला दूसरा आधार यह है कि डॉक्टर-पीडब्लू 2 के साक्ष्य के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्य की समवर्ती खोज, जिसने अपीलकर्ता की जांच की है, जिन्होंने उसकी चोटों की प्रकृति के संबंध में टिप्पणियाँ की हैं जिन्हें इस निर्णय के बाद के भाग में दर्ज किया जाएगा।

5. दावेदार-अपीलकर्ता की जांच करने पर, डॉक्टर- पीडब्लू 2 ने राय दी कि वह बैठने में सक्षम नहीं है, उसकी विकलांगता 70% पर सुनिश्चित की गई है, इसलिए, वह फर्श पर आराम से और सही सीमा पर क्रॉस लेग करके बैठने में सक्षम नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में उसे लगी गंभीर चोटों के कारण मौजूद 850 लिगामेंट अस्थिरता की मूवमेंट (जियोनीमीटर) की फ्लेक्सिम विकृति को ठीक किया गया। इसलिए, PW2 ने दावेदार-अपीलकर्ता की स्थायी विकलांगता का आकलन 70% किया है और इस आशय से उसने Ex पी12-विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया है। और उसे कमाई की हानि, दर्द और पीड़ा, सुविधाओं की हानि और मानसिक पीड़ा के तहत उचित और उचित मुआवजा देने के दावे के औचित्य में एक प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किया गया था। रिकॉर्ड पर विकलांगता प्रमाण पत्र के रूप में साक्ष्य के उपरोक्त महत्वपूर्ण भारा पर उच्च न्यायालय द्वारा उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया है, हालांकि यह रिकॉर्ड पर साक्ष्य की पुनः सराहना करते हुए ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष से सहमत है। मुआवज़े की मात्रा के संबंध में मामले के कानूनी पहलू को खारिज करने और मानवीय दर्द और पीड़ा और दावेदार के निजी जीवन की खुशी और आनंद से वंचित करने के लिए मुआवज़ा देने की आवश्यकता है। जो मुआवज़ा दिया जाएगा उसकी तुलना मानवीय पीड़ा या व्यक्तिगत अभाव से नहीं की जा सकती, जैसा कि इस न्यायालय ने आर.डी. हट्टंगडी बनाम पेस्ट कंट्रोल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य के मामले में देखा था।

6. ट्रिब्यूनल और अपीलीय न्यायालय दोनों को पैसे के मूल्य में गिरावट पर विचार करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए इन पुरस्कारों के निरंतर पुनर्मूल्यांकन और पैटर्न में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर क्षति के आवधिक पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, जहां विकलांगता आसानी से पहचानी जा सकती है और बड़े पैमाने पर नहीं होती है। व्यक्तिगत मामलों में भिन्नताएं, जैसा कि आर.डी. हट्टंगडी (उपरोक्त) के मामले में हुआ था। इसलिए, दावेदार-अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का कहना है कि दर्द और पीड़ा, दोनों अंगों को खोने के कारण सुविधाओं की हानि, जो प्रासंगिक महत्वपूर्ण भौतिक तथ्य हैं, जिन्हें ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय दोनों ने निर्धारित करते समय पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। दावेदार के पक्ष में मुआवजा देते समय उपरोक्त मदों के तहत न्यायसंगत और उचित मुआवजा देते समय यह चीजें नजरअदांज की गई है। इसलिए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय से पूर्वोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी सिद्धांतों को लागू करके उपरोक्त शीर्षकों के तहत उचित और उचित मुआवजा देने का अनुरोध किया। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने आर.डी. हट्टंगडी (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित सिद्धांत पर सही ढंग से भरोसा किया है, जिसे गोविंद यादव बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में दोहराया गया था, आर.डी. हट्टंगडी मामले के कुछ प्रासंगिक पैराग्राफ निकालना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं:

"10. इसमें कोई विवाद नहीं है कि दुर्घटना के कारण अपीलकर्ता, जो एक सक्रिय प्रैक्टिसिंग वकील था, लगी चोटों के कारण अशक्त हो गया है। इस पृष्ठभूमि में दर्द के लिए मुआवजे की सटीक राशि का आकलन करना वास्तव में मुश्किल है और अपीलकर्ता को पीड़ा का सामना करना पड़ा और वह जीवन भर विकलांग हो गया। मुआवजे की कोई भी राशि अपीलकर्ता के शारीरिक ढांचे को बहाल नहीं कर सकती। इसीलिए अदालतों द्वारा यह कहा गया है कि जब भी कोई राशि किसी भी चोट के लिए देय मुआवजे के रूप में निर्धारित की जाती है किसी दुर्घटना के दौरान, उद्देश्य ऐसी चोट की भरपाई करना है "जहाँ तक पैसा इसकी भरपाई कर सकता है" क्योंकि पैसे की तुलना मानवीय कष्टों या व्यक्तिगत अभावों से करना असंभव है। पैसा एक बिखरे हुए और टूटे हुए शारिरिक ढांचे को नया नहीं कर सकता है।

11. वार्ड बनाम जेम्स [1965] 1 ऑल ई.आर. 563 मामले में यह कहा गया था:

यद्यपि आप इतने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को उसके "खोए हुए वर्षों" के लिए ज्यादा कुछ नहीं दे सकते, तथापि, आप उसकी छोटी अवधि के दौरान, अर्थात, उसके अपेक्षित "जीवित रहने के वर्षों" के दौरान, उसके नुकसान की भरपाई

कर सकते हैं। आप उस दौरान उसकी कमाई के नुकसान और इलाज, देखभाल और उपस्थिति की लागत के लिए उसे मुआवजा दे सकते हैं। लेकिन आप उसे असहाय अशक्त बनाये जाने की क्षतिपूर्ति कैसे कर सकते हैं? वह मस्तिष्क की चोट के कारण शेष दिनों के लिए बेहोश हो सकता है, या पीठ की चोट के कारण अपने बिस्तर से उठने में असमर्थ हो सकता है। उसने वह सब कुछ खो दिया है जो जीवन को सार्थक बनाता है। पैसा उसके लिए अच्छा नहीं है फिर भी न्यायाधीशों और जूरी को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा और उसे वही देना होगा जो वे उचित समझते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे इसे लगभग अघुलनशील पाते हैं। उनसे बेहिसाब हिसाब मांगा जा रहा है। यह आंकड़ा अधिकांश भाग के लिए एक पारंपरिक राशि होने के लिए बाध्य है। न्यायाधीशों ने एक पैटर्न तैयार किया है, और वे इसे पैसे के मूल्य में बदलाव के अनुरूप रखते हैं।"

7. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि दावेदार-अपीलकर्ता को वैवाहिक संभावनाएं जीवन के आनंद से भी वंचित किया गया है। इसके अलावा, आक्षेपित फैसले में उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्ष से पता चलता है कि अपीलकर्ता घुटने की चोटों और स्थायी विकलांगता और घुटने की हड्डियों के खराब होने के कारण, बैसाखी के बिना चलने में

असमर्थ है और वह पीड़ित है चलते समय गंभीर दर्द होता है और इसके अलावा दुर्घटना में लगी चोटों के कारण दोनों पैरों की मोटाई भी कम हो गई है और उस पर कई सर्जरी की गई हैं। इस प्रासंगिक पहलू को ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए था। इसके अलावा, उसे जीवन भर चलने-फिरने के लिए बैसाखियों का उपयोग करना पड़ता है, जिसे उसे समय समय पर खरीदना पड़ता है, जिसकी लागत का फैसला ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है। इसलिए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय से उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उचित मुआवजा देने का अनुरोध किया है।

8. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 2-बीमा कंपनी की ओर से विद्वान वकील सुश्री मंजीत चावला ने यह कहते हुए आक्षेपित निर्णय और पंचाट को उचित ठहराने की मांग की कि उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर दलीलों और सबूतों की फिर से सराहना की। आक्षेपित निर्णय में उल्लिखित विभिन्न मदों जैसे दर्द और पीड़ा, स्थायी विकलांगता, चिकित्सा व्यय, परिवहन व्यय, अतिरिक्त पोषण, भविष्य के कैरियर की हानि और विवाह की संभावनाओं की हानि के तहत मुआवजे में अत्यधिक वृद्धि की है। इसलिए, यह इस न्यायालय के लिए मुआवज़ा बढ़ाने का उपयुक्त मामला नहीं है जैसा कि दावेदार-अपीलकर्ता ने इस मामले में प्रार्थना की है।

9. इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील का कहना है कि दावेदार-अपीलकर्ता कॉलेज में जाकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है और अपनी पढ़ाई पूरी होने पर सार्वजनिक रोजगार या वैकल्पिक निजी रोजगार प्राप्त कर सकती है। ऐसी परिस्थितियों में, जैसा कि दावेदार-अपीलकर्ता द्वारा दावा किया गया है, कमाई के नुकसान या भविष्य की संभावनाओं के तहत मुआवजे में वृद्धि की मांग करना कानून में उचित नहीं है। इसलिए, प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वकील ने सिविल अपील को खारिज करने की प्रार्थना की है।

10. उपरोक्त प्रतिद्वंद्वी तथ्यात्मक और कानूनी तर्कों के संदर्भ में, इस न्यायालय को यह जांचना आवश्यक है: -

1) क्या दावेदार-अपीलकर्ता निम्नलिखित शीर्षकों के तहत मुआवजे में वृद्धि का हकदार है, अर्थात् आय की हानि, दर्द और पीड़ा, सुख सुविधाओं की हानि, विवाह की संभावनाओं के आनंद की हानि और बैसाखी की लागत?

2) क्या पंचाट होना चाहिए?

11. प्रथम प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित कारणों से दावेदार-अपीलकर्ता के पक्ष में दिया जाना आवश्यक है:-

दुर्घटना में अपीलकर्ता को लगी निम्नलिखित चोटों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जो एक निर्विवाद तथ्य है: -

दाहिना निचला अंग: हाइपरट्रॉफिक निशान जांघ के बाहर से लेकर दाहिने पैर के बाहरी 2/3 भाग तक फैला हुआ है। दाहिने पैर के एम/3 पर संवेदनशीलता में कमी।

बायां पैर: बाएं पैर के मध्य तीसरे से दूरस्थ तीसरे भाग पर हाइपरट्रॉफिक निशान और धब्बेदार क्षेत्रों के साथ निशान पर संवेदना कम हो गई।

दोनों पैरों की मांसपेशियाँ नष्ट हो रही हैं।

दायां टखना: पहले भाग के दाहिने टखने की विषुव विकृति। लगभग 10 वें पैर की उंगलियों के द्वितीय जोड़ों की फ्लेक्सिम विकृति को ठीक किया गया।

12. डॉक्टर-पीडब्लू 2 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि अपीलकर्ता के दोनों पैरों की हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ है, घुटने मोड़ना 25 डिग्री से 85 डिग्री के बीच सीमित है और पैर पूरी तरह से नहीं खींचे जा सकते हैं और घुटने की हड्डियाँ वे एकजुट नहीं हैं और अपीलकर्ता बैसाखी के बिना नहीं चल सकता। डॉक्टर ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता को चलते समय गंभीर दर्द हो रहा है और इसके अलावा अपीलकर्ता के दोनों पैरों की मोटाई भी कम हो गई है।

13. डॉक्टर-पीडब्लू2 के उपरोक्त साक्ष्य को ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा सहमति व्यक्त की गई है,

उच्च न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलकर्ता ने स्थायी विकलांगता बरकरार रखी है, यह इसके द्वारा निर्धारित सिद्धांत राज कुमार बनाम अजय कुमार और अन्य* के मामले में न्यायालय पैरा 12 के अनुरूप है। जो इस प्रकार है:

"12. इसलिए, ट्रिब्यूनल को पहले यह तय करना होगा कि क्या कोई स्थायी विकलांगता है और यदि हां, तो ऐसी स्थायी विकलांगता की सीमा क्या है। इसका मतलब है कि ट्रिब्यूनल को साक्ष्य के संदर्भ में विचार करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए:

(i) क्या विकलांगता स्थायी है या अस्थायी;

(ii) यदि विकलांगता स्थायी है, चाहे वह स्थायी पूर्ण विकलांगता हो या स्थायी आंशिक विकलांगता;

(iii) यदि विकलांगता प्रतिशत को किसी विशिष्ट अंग के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, तो अंग की ऐसी विकलांगता का प्रभाव पूरे शरीर की कार्यप्रणाली पर पड़ता है, अर्थात व्यक्ति को होने वाली स्थायी विकलांगता होती है।

यदि ट्रिब्यूनल यह निष्कर्ष निकालता है कि कोई स्थायी विकलांगता नहीं है तो आगे बढ़ने और भविष्य की कमाई क्षमता के नुकसान का निर्धारण करने का कोई

सवाल ही नहीं है। लेकिन यदि न्यायाधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि स्थायी विकलांगता है तो वह इसकी सीमा का पता लगाने के लिए आगे बढ़ेगा। चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर ट्रिब्यूनल दावेदार की स्थायी विकलांगता की वास्तविक सीमा का पता लगाने के बाद, उसे यह निर्धारित करना होगा कि क्या ऐसी स्थायी विकलांगता ने उसकी कमाई की क्षमता को प्रभावित किया है या प्रभावित करेगा।"

14. अपीलकर्ता के दोनों पैरों में हुए फ्रैक्चर के संदर्भ में रिकॉर्ड पर मौजूद चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर उच्च न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसे 70% स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा है और इसलिए किसी दस्तावेज़ रिकॉर्ड के अभाव में क्योंकि वह एक छात्रा थी आक्षेपित निर्णय में कमाई की हानि का शीर्ष उसे 6,000/- रुपये की मासिक अनुमानित आय को ध्यान में रखते हुए मुआवजे से सम्मानित किया गया। आर.डी. हट्टंगडी (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर नीचे की अदालतों की यह धारणा निचले स्तर पर है। उक्त सिद्धांत गोविंद यादव (उपरोक्त) में दोहराया गया है। आर.डी. हट्टंगडी से प्रासंगिक पैरा नीचे दिया गया है:

14. हेल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चतुर्थ संस्करण, खंड 12 में गैर-आर्थिक हानि के संबंध में पृष्ठ 446 पर कहा गया है:

गैर-आर्थिक हानि; तरिका/प्रतिरूप। दर्द और पीड़ा और सुविधा की हानि के लिए दी जाने वाली क्षतिपूर्ति एक पारंपरिक राशि होती है जिसे वह राशि माना जाता है जिसे समाज उचित मानता है, पिछले निर्णयों के आलोक में अदालतों द्वारा निष्पक्षता की व्याख्या की जाती है। इस प्रकार पारंपरिक सिद्धांतों का एक सेट विकसित किया गया है जो विभिन्न चोटों की तुलनात्मक गंभीरता के लिए एक अनंतिम मार्गदर्शन प्रदान करता है, और नुकसान की एक श्रेणी का संकेत देता है जिसमें वर्तमान में एक विशेष चोट आएगी। वादी की विशेष परिस्थितियाँ, जिसमें उसकी उम्र और उसे होने वाली कोई भी असामान्य कमी शामिल है, पंचाट की वास्तविक राशि में परिलक्षित होती है।

पैसे के मूल्य में गिरावट से इन पुरस्कारों का निरंतर पुनर्मूल्यांकन होता है और पैटर्न में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर क्षति का समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन होता है, जहां विकलांगता आसानी से पहचानी जा सकती है और व्यक्तिगत मामलों में बड़े बदलावों के अधीन नहीं होती है।

(न्यायालय द्वारा जोर दिया गया)

15. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता एक मेधावी छात्रा है क्योंकि उसने 10 वीं कक्षा में

प्रथम रैंक हासिल की है, बुनियादी या मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए शैक्षिक करियर के मामले में उसके पास बेहतर भविष्य होगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में और उसे उपयुक्त सार्वजनिक या निजी रोजगार मिल सकता था, लेकिन दुर्घटना में लगी चोटों के कारण वह स्थायी विकलांगता के कारण वह अवसर खो गई और इसलिए, वह मुआवजे की हकदार है। राज कुमार, आर.डी. हट्टंगडी और गोविंद यादव (उपरोक्त) के मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून।

16. इसके अलावा, इस निर्विवाद तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दुर्घटना की घटना के बाद से देश में धन की मुद्रास्फीति हुई है, दावेदार-अपीलकर्ता को मुआवजा देते समय ट्रिब्यूनल और अपीलीय न्यायालय द्वारा इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। गोविंद यादव के मामले में इस अदालत द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुसार, जिसने रेशमा कुमारी बनाम मदन मोहन मामले की स्थिति को दोहराया है, जिसका प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है:

> "46. भारतीय संदर्भ में आश्रितों की शिक्षा और नौकरी की प्रकृति सहित कई अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। बदली हुई सामाजिक परिस्थितियों और वैश्विक परिदृश्य के मद्देनजर, न केवल भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखना होगा कर्मचारी की स्थिति, उसकी शैक्षिक योग्यता; उसका पिछला प्रदर्शन, बल्कि अन्य

प्रासंगिक कारक, अर्थात् उच्च वेतन और भत्ते जो इन दिनों निजी कंपनियों द्वारा दिए जा रहे हैं। वास्तव में गुणक का निर्धारण करते समय यह न्यायालय ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जशुबेन में माना कि महंगाई भत्ता और उसके संबंध में भत्ते, जिनसे परिवार को मासिक लाभ प्राप्त होता, को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

17. उसे मुआवजा देते समय इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि दुर्घटना के समय अपीलकर्ता प्रतिभाशाली छात्रा थी। इसलिए, इस मद के तहत मुआवजा देने के उद्देश्य से ट्रिब्यूनल द्वारा 6,000/- मासिक अनुमानित आय के रूप में लेना बहुत कम राशि है। प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता अभी भी अपनी शिक्षा पूरी कर सकती है और रोजगार पा सकती है और इसलिए, 'आय की हानि' और 'भविष्य की संभावनाओं' के तहत मुआवजे की राशि बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां यह दोहराना उचित है कि दावेदार अपीलकर्ता को दुर्घटना के कारण काफी दर्द और पीड़ा से गुजरना पड़ा है, जिससे उसके दोनों पैर बेकार हो गए हैं। इससे उसकी शादी सहित भविष्य की संभावनाओं की गुंजाइश काफी कम हो गई है। इसके अलावा, एक अपकृत्यकर्ता दावेदार-अपीलकर्ता के करियर की शर्तों को निर्धारित करने का हकदार नहीं है, जैसा कि के. नरसिम्हा मूर्ति बनाम मैनेजर, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एएनएफ आईएलआर

2004 कर्नाटक 2471 के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना है। जिसका प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है:

> "41... इसके अलावा, इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि यह यातना देने वाले या उस व्यक्ति का अधिकार नहीं है, जिसने अधिनियम के तहत या उसके तहत यातना देने वाले के दायित्व को अपने ऊपर ले लिया है, यह निर्देशित करने का कि घायल व्यक्ति को क्या करना चाहिए कोई अन्य कार्य, मैनुअल या अन्यथा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दर्द और असुविधा के साथ हो सकता है, ताकि उसके दायित्व को कम किया जा सके। इस तरह का आग्रह कानून में अस्थिर है और यदि ऐसा मामला है, तो यह घायल व्यक्ति के बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा । इस मामले में, अपीलकर्ता ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वह खुद को दर्द और पीड़ा, पीड़ा और परेशानी के अधीन किए बिना कोई भी काम करने में असमर्थ हो जाता है, शारीरिक या अन्य। किसी दुर्घटना में, यदि कोई व्यक्ति विकलांग हो जाता है वह काम जो वह दुर्घटना से पहले कर रहा था, कि उसके पास किसी अन्य चीज़ के लिए कोई प्रतिभा, कौशल, अनुभव या प्रशिक्षण नहीं है और वह कोई भी काम, मैनुअल या लिपिकीय काम पाने में असमर्थ

है, ऐसे व्यक्ति ने सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए पहले से मौजूद अपनी कमाई की सारी क्षमता खो दी है। और उसे कुल नुकसान के आधार पर मुआवजा दिया जाना आवश्यक है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में हम डेनियल बनाम सर रॉबर्ट मैक अल्पाइन एंड संस लिमिटेड और ब्लेयर बनाम एफजेसी लिली (मरीन) लिमिटेड के निर्णयों से समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे, अपीलकर्ता की आय अर्जित करने में शारीरिक अक्षमता अस्थायी नहीं है, बल्कि प्रदर्शनी पी. 43 के अनुसार स्थायी और पूर्ण है। तीसरा, यह नहीं कहा जा सकता है कि चूंकि अपीलकर्ता ने संपूर्ण के संबंध में केवल 54% स्थायी शारीरिक विकलांगता बरकरार रखी है। पी.डब्ल्यू के अनुसार शरीर 3, न्यायालय को कमाई क्षमता के नुकसान का आकलन करते समय कार्यात्मक विकलांगता को भी 54% पर ही ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी परिकल्पना तर्कसंगत नहीं है और न ही इसे कानून की दृष्टि से वैध माना जा सकता है। एक घायल व्यक्ति को उस नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता है जो उसे शारीरिक चोट के परिणामस्वरूप होता है, न कि शारीरिक चोट के लिए। दूसरे शब्दों में, मुआवजा केवल दुर्घटना के कारण हुई हानि के लिए धन के समतुल्य के रूप में दिया जाता है,

जहां तक धन की प्रकृति नुकसान के लिए अनुमति देती है। किसी दुर्घटना में, यदि कोई व्यक्ति एक अंग या आंख खो देता है या घायल हो जाता है, तो न्यायालय अंगों की हानि या शारीरिक चोट के लिए क्षति की गणना करते समय, एक अंग या आंख को अलग से महत्व नहीं देता है, बल्कि केवल नुकसान की समग्रता को महत्व देता है। नुकसान में जीवन की सुविधाओं की हानि और दर्द और पीड़ा का नुकसान शामिल है: जीवन की अच्छी चीजों की हानि, जीवन की खुशियाँ और दर्द और संकट का सकारात्मक नुकसान।

18. इसके अलावा, रेशमा कुमारी (उपरोक्त) के मामले में यह माना गया है कि आय की भविष्य की संभावना के तहत मुआवजा देते समय कुछ प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है:

27. भविष्य की कमाई के संभावित नुकसान के संबंध में मुआवजे के निर्धारण के लिए लागू की जाने वाली आवश्यक पद्धति का प्रश्न, हालांकि, जहां तक संभव हो कुछ सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। एक व्यक्ति के पास एक उज्ज्वल भविष्य की संभावना हो सकती है; उसके पास हो सकता है तुरंत पदोन्नति के पात्र बनें; तत्काल वेतन संशोधन की संभावना हो

सकती है, जबकि दूसरे में रोजगार की प्रकृति ऐसी थी कि वह सेवा में जारी नहीं रह सकता था; रोजगार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पदोन्नति की संभावना दूर हो सकती है या दूरस्थ। इसलिए, किसी भी अदालत के लिए कठोर परीक्षण निर्धारित करना मुश्किल है, जिसे सभी स्थितियों में लागू किया जाना चाहिए। अलग-अलग विचार हैं। कुछ मामलों में यह सुझाव दिया गया है कि कुछ प्रकार की परिकल्पना या अनुमान अपरिहार्य हो सकता है, सम्भव है।

19. इसलिए, उपरोक्त मामले में निर्धारित सिद्धांतों के प्रकाश में, यह इस न्यायालय के लिए उचित और न्यायसंगत होगा, और उसके पिछले परिणामों को ध्यान में रखते हुए हम आय की हानि के मद के तहत उचित और न्यायसंगत मुआवजे की गणना के लिए उसकी मासिक अनुमानित आय के रूप में 10,000/- रु लेते हैं इसके अलावा, उच्च न्यायालय पूर्वोक्त संदर्भित मामलों के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर आय की भविष्य की संभावनाओं पर विचार करने में विफल रहा है। इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा इस शीर्ष के तहत भी पुनः वृद्धि की मांग करना उचित है और हम मानते हैं कि दावेदार-अपीलकर्ता संतोष देवी के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुसार इस शीर्ष के तहत 50% वृद्धि का हकदार है (उपरोक्त)। प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है:

13. सरला वर्मा के मामले (उपरोक्त) में, अन्य दो न्यायाधीशों की पीठ ने मोटर दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों में देय मुआवजे का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक विभिन्न कारकों पर विचार किया, विभिन्न मामलों में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त विचारों में स्पष्ट भिन्नता देखी गई, बड़ी संख्या में उदाहरणों का हवाला दिया गया जिसमें यूपी एसआरटीसी बनाम त्रिलोक चंद्रा (1996) 4 एससीसी 362, नेंस बनाम ब्रिटिश कोलंबिया इलेक्ट्रिक रेलवे कंपनी लिमिटेड 1951 एसी 601, डेविस बनाम पॉवेल डफ्रिन एसोसिएटेड कोलियरीज लिमिटेड: 1942 एसी 601 के फैसले शामिल हैं और इसे सीमित करने का प्रयास किया गया है। विभिन्न शीर्षकों के तहत स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला निर्धारित करके मुआवजे के पंचाट के मामले में ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालयों द्वारा विवेक का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

(i) भविष्यवर्ती आय की सम्भवाना में वृद्धि

सुसम्मा थॉमस में इस न्यायालय ने आय में लगभग 100% की वृद्धि की, सरला दीक्षित में आय में केवल 50% की वृद्धि हुई और अबाती बेजबरुआ में आय में मात्र 7% की वृद्धि हुई। असंभवताओं और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, हम एक नियम के रूप में मृतक की वास्तविक वेतन आय में भविष्य की संभावनाओं के लिए वास्तविक वेतन का 50% जोड़ने को अपनाने के पक्ष में हैं, जहां मृतक के पास स्थायी नौकरी थी और वह

40 साल से कम आयु का था। (जहां वार्षिक आय कर योग्य सीमा में है, वहां "वास्तविक वेतन" शब्द को "वास्तविक वेतन कम कर" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए)। यदि मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष है तो जोड़ केवल 30% होना चाहिए। जहां मृतक की आयु 50 वर्ष से अधिक हो, वहां कोई जोड़ नहीं होना चाहिए।

हालाँकि साक्ष्य वृद्धि के अलग-अलग प्रतिशत का संकेत दे सकते हैं, लेकिन अलग-अलग मानदंडों को लागू करने या गणना के विभिन्न तरीकों को अपनाने से बचने के लिए जोड़ को मानकीकृत करना आवश्यक है। जहां मृतक स्व-रोज़गार था या एक निश्चित वेतन पर था (वार्षिक वेतन वृद्धि आदि के प्रावधान के बिना), अदालतें आमतौर पर मृत्यु के समय केवल वास्तविक आय ही लेंगी। इससे हटना केवल विशेष परिस्थितियों वाले दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए।

इसलिए, दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, इस मद के तहत मुआवजे की कुल राशि की गणना 22,68,000/- रुपये की जाती है। [(रु.10,000/-x 70/100 + 10,000 x 70/100 x 50/100) x 12 x 18]

20. सिर दर्द, पीड़ा और मानसिक पीड़ा के मद के तहत मुआवजा ट्रिब्यूनल द्वारा पारित पंचाट के साथ समवर्ती निष्कर्ष दर्ज करने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। हालाँकि, नीचे की अदालतों ने रुपये

का पंचाट देते समय अपीलकर्ता द्वारा झेली गई स्थायी विकलांगता की प्रकृति को दर्ज नहीं किया है। इस मद के तहत 1,00,000/- जो कि बहुत कम राशि है और आर.डी. हट्टंगडी और गोविंद यादव मामलों (उपरोक्त) के फैसले के विपरीत है। गोविंद यादव मामले के प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं:

> "25. पैर काटने के कारण होने वाले दर्द, पीड़ा और आघात के लिए ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया मुआवजा बहुत कम था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता तीन महीने से अधिक समय तक अस्पताल में रहा था। यह संभव नहीं है न्यायाधिकरणों और अदालतों के लिए उस व्यक्ति के दर्द और आघात का सटीक आकलन करना जिसका दुर्घटना के परिणामस्वरूप अंग काट दिया गया हो। भले ही दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को कृत्रिम अंग मिल जाए, वह विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं और सामाजिक समस्याओं से पीड़ित होगा जीवन भर समाज में उसका अलग स्थान रहेगा। इसलिए, ऐसे सभी मामलों में, न्यायाधिकरण और अदालतों को मुआवजे की राशि तय करने के उद्देश्य से एक व्यापक अनुमान लगाना चाहिए।

26. माना कि दुर्घटना के समय अपीलकर्ता 24 वर्ष का युवक था। शेष जीवन में वह अपना सामान्य कार्य न कर पाने का सदमा झेलेगा। इसलिए, हमें लगता है कि पैर के विच्छेदन के कारण हुए दर्द, पीड़ा और आघात के बदले उसे 1,50,000 रुपये का पंचाट देकर न्याय का उद्देश्य पूरा किया जाएगा।"

इसलिए, इस मद के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 2,00,000/- रुपये किया जाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर-पीडब्ल्यू 2 ने राय दी है कि बैसाखी के सहारे चलने के समय, दावेदार-अपीलकर्ता को स्थायी रूप से दर्द होगा। इसलिए, इस मद के तहत इसे 1,00,000/- रुपये से बढ़ाकर 2,00,000/- रुपये किया जाना है।

21. नीचे की अदालतों द्वारा 1,00,000/- रुपये की सुविधा और परिचर शुल्क की हानि भी बहुत कम है क्योंकि अपीलकर्ता ने अपने दोनों पैरों की सुविधा स्थायी रूप से खो दी है। अपने पूरे जीवन में चलने, बैठने, दौड़ने और पढ़ने के लिए और विशेष रूप से, अधिक उम्र में, उसे शौचालय और बाथरूम जाने के और बैठने या घूमने के समय सहायता देने के लिए परिचारक की आवश्यकता होगी। इसलिए, इस अदालत द्वारा गोविंद यादव मामले (उपरोक्त) में निर्धारित सिद्धांत के आधार पर इस मद में मुआवजे

को 1,00,000/- रुपये से बढ़ाकर 2,00,000/- रुपये करने की आवश्यकता है, जिसका प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार पढ़ता है:

> ''27. सुविधाओं के नुकसान के लिए ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया मुआवजा भी बहुत कम था। यह केवल कल्पना का विषय हो सकता है कि अपीलकर्ता को अपना शेष जीवन एक कृत्रिम पैर के साथ कैसे जीना होगा। अपीलकर्ता हो सकता है कम से कम 50 वर्ष तक जीवित रहने की उम्मीद है। इस अवधि के दौरान वह एक सामान्य इंसान की तरह नहीं रह पाएगा और जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा। उसकी शादी की संभावनाएं काफी कम हो गई हैं। इसलिए, यह उचित और उचित होगा जीवन की सुविधाओं और आनंद की हानि के लिए उसे 1,50,000 रुपये की राशि का पंचाट दिया जाए।''

22. 'जीवन के आनंद की हानि और विवाह की संभावनाओं' के मद में दी गई मुआवजे की राशि रु. 2,00,000/- पूरी तरह से अपर्याप्त है क्योंकि उसकी शादी की संभावना काफी कम हो गई है और स्थायी विकलांगता के कारण वह जीवन के आनंद से वंचित हो जाएगी। इसलिए, मुआवजे को 2,00,000/- रुपये से बढ़ाकर 3,00,000/- रुपये करना उचित और उचित होगा। जहां तक समय-समय पर बैसाखी खरीदने का

सवाल है, तो 50,000/- रुपये की राशि का पंचाट देना उचित और उचित होगा।

23. इसके अलावा, दुर्घटना 11.4.2005 को हुई थी और दावेदार-अपीलकर्ता तब से न्याय के लिए लड़ रहा है, पहले मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में, फिर उच्च न्यायालय में और अंत में हमारे सामने। इसलिए, हम मानते हैं कि बैरम प्रसाद बनाम कुणाल साहा और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुसार वह मुकदमे की लागत की सही हकदार है। इसलिए, हम 'मुकदमे की लागत' के मद में 25000/- रुपये की राशि प्रदान करते हैं।

24. इस प्रकार, इस अपील में दावेदार-अपीलकर्ता दिल्ली नगर निगम, दिल्ली बनाम उपहार त्रासदी पीड़ित संघ एवं अन्य में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के आधार पर आवेदन दाखिल करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक प्रति वर्ष 9% ब्याज के साथ मुआवजे के रूप में 30,93,000/- की कुल राशि का हकदार है।

25. बीमा कंपनी को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर दी गई राशि का 50% आनुपातिक ब्याज के साथ, यदि पहले ही भुगतान कर दिया गया है तो राशि काटकर, अपीलकर्ता की, पसंद के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में 3 वर्ष की अवधि के लिए जमा कर दे। उक्त अवधि के दौरान, यदि वह अपनी

संपत्ति के विकास सहित अपने व्यक्तिगत या किसी अन्य खर्च के लिए एक हिस्सा या पूरी जमा राशि निकालना चाहती है, तो वह जमा राशि जारी करने के लिए ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है, जो हो सकता है इस पर विचार किया जाए और इस संबंध में उचित आदेश पारित किया जाए।

आनुपातिक ब्याज के साथ दी गई शेष 50% राशि अपीलकर्ता/दावेदार को इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान की जाएगी। बीमा कंपनी को इसके बाद पांच सप्ताह के भीतर इस अदालत के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

26. तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। खर्चो के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं।

राजेन्द्र प्रसाद

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिंशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री संजय कुमार मीना द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सिमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है औ किसी अन्य उदेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदश्यों के लिये निर्ण्य का अग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य से भी अग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।